एक बड़ी कटौती: कॉर्पोरेट कर में कटौती

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

21 सितम्बर, 2019

"कर कटौती ने कॉर्पोरेट भारत को उत्साहित किया है, लेकिन इससे निपटने के लिए राजकोषीय समस्या बीच में खड़ी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट करों में बड़ी कटौती की और जुलाई में पेश किए गए बजट में कुछ बाजार विरोधी प्रस्तावों को ठीक करने की घोषणा के साथ दीपावली के लिए तोहफा देने की शुरुआत कर दी है। कॉर्पोरेट करों में कटौती करने का कदम, जिसके लिए सरकार द्वारा पहले ही एक अध्यादेश जारी किया जा चुका है, 1997 के भाव-बोध वाले 'ड्रीम बजट' से मिलता जुलता है, जहाँ तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बड़े उत्साह के साथ करों में कटौती की थी।

कॉर्पोरेट टैक्स की दर में छूट का लाभ नहीं लेने वाली कंपनियों के लिए 30% से 22% तक कटौती की गई है इसका मतलब है कि ऐसी कंपनियों के लिए प्रभावी कर की दर वर्तमान में 34.94% से गिरकर 25.17% हो जाएगी जो वास्तव में एक महत्वपूर्ण बचत है।

इसी तरह, 1 अक्टूबर के बाद शामिल होने वाली कंपनियों और जिनकी परियोजनाओं को 31 मार्च, 2023 से पहले चालू कर दिया जाएगा, कर की दर 15% (वर्तमान में 25% की तुलना में) जितनी कम होगी। कंपनियों की इस श्रेणी के लिए प्रभावी कर की दर 17.01% होगी, जो अब तक की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत कम है।

इस कदम के पीछे का विचार स्पष्ट रूप से निजी निवेश उत्पन्न करना है, जो अब कम कीमत पर है, लेकिन एक छिपी हुई मंशा यह भी हो सकती है कि विदेशी निवेशकों को चीन और यू.एस. के बीच टैरिफ युद्ध द्वारा बाधित उनकी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के लिए वैकल्पिक साइटों की तलाश में आकर्षित किया जाए।

इन कटौती के साथ, सरकार ने कॉर्पोरेट भारत की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है। दायित्व अब ताजा निवेश के प्रवाह को ही सिर्फ नहीं बढ़ाना है बल्कि उपभोक्ताओं और निवेशकों को करों से लाभ भी प्रदान करना है।

अब सवाल उठता है कि इस टैक्स छूट के कारण सरकार और वित्तीय घाटा किस स्थिति में आ जाएगा? सुश्री सीतारमण ने कहा कि राजस्व सीमा 1,45,000 करोड़ है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से बजट में राजस्व के अधिक आकलन और इस वर्ष अब तक के कर संग्रह के संदर्भ में कम प्रदर्शन के संदर्भ में।

2019-20 के बजट में 16.49 लाख करोड़ के शुद्ध कर राजस्व का अनुमान लगाया गया है, जो 2018-19 में 13.16 लाख करोड़ के वास्तविक राजस्व से अधिक महत्वाकांक्षी 25% की वृद्धि का अनुमान है। यदि राजस्व की सीमा को अब इस अवास्तविक बजट लक्ष्य के विरुद्ध तौला जाता है, जिस पर राजकोषीय अंकगणित आधारित है, तो इस वर्ष अनुमानित घाटे के लिए दृष्टिकोण निश्चित रूप से डरावना होगा।

निश्चित रूप से यह कहना गलत नहीं होगा कि इस वित्त वर्ष के लिए 3.3% का घाटे का लक्ष्य अप्राप्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से लाभांश के रूप में प्राप्त 1.75 लाख करोड़ रूपए का इनाम स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करना है, तो राजस्व के मूल अति आकलन से अंतर को पाटना होगा।

सरकार के लिए खुला एक मार्ग विनिवेश पर बड़ा है, जहां उसने पहले ही इस वर्ष के लिए 1,05,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा मूल अंकगणित बेहतर ढंग से कार्य करे, तो वास्तविक आय इस राजकोषीय से दोगुनी होनी चाहिए।

हालांकि, यह आसान नहीं होगा, लेकिन करना पड़ेगा। मध्यम अवधि में कॉर्पोरेट कर में कटौती निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है, लेकिन अल्पावधि में, जब तक राजस्व वापस नहीं बढ़ता, सरकार के लिये राजकोषीय समस्या बढ़ने वाली है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कॉर्पोरेट कर में कटौती का क्या अर्थ है

लेखक – प्रशांत पेरुमल (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

21 सितम्बर, 2019

"कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती आर्थिक वृद्धि में मंदी से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की एक श्रृंखला का हिस्सा है।"

अर्थव्यवस्था में हलचल मचाने के लिए अभी तक के अपने साहसिक कार्यक्रम में, सरकार ने हाल ही में घरेलू फर्मों और नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर को 10 से 12 प्रतिशत तक कम करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है, जो प्रभावी रूप से अपने प्रतिस्पर्धी एशियाई साथियों के साथ भारत की कर दरों को बराबर लाने के संदर्भ में भी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरचार्ज में शामिल घरेलू कॉर्पोरेट्स के लिए प्रभावी कर की दर 34.94% से गिरकर 25.17% हो जाएगी, अगर वे किसी भी अन्य कर से बचना बंद कर देते हैं।

1 अक्टूबर, 2019 के बाद स्थापित होने वाली नई विनिर्माण कंपनियों के लिए और 31 मार्च, 2023 तक परिचालन शुरू होने से प्रभावी कर दर 29.1% से घटकर 17% रह जाएगी।

अब तक की कहानी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अन्य बातों के अलावा, कॉर्पोरेट कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा की, इस प्रकार निगमों पर प्रभावी कर दर (विभिन्न उपकरों और अधिभार सहित) को 35% से 25% तक लाया गया।

नई कॉर्पोरेट कर नीति के तहत, भारत में अक्टूबर से शुरू होने वाली और मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली नई कंपनियों पर 17% की प्रभावी दर से कर लगाया जाएगा।

सरकार के निर्णय के बाद, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 5% से अधिक हो गए, जो एक दशक में सबसे बड़ी बढ़त है।

सरकार टैक्स क्यों काट रही है?

कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती आर्थिक वृद्धि में मंदी से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जो जून तिमाही में लगातार पांच तिमाहियों से गिरकर 5% हो गई है।

कर कटौती के पीछे सबसे तात्कालिक कारण नाराजगी हो सकती है जो विभिन्न कॉर्पोरेट घरानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ दिखाई है। उदाहरण के लिए, जुलाई में बजट के दौरान सरकार ने निवेशकों पर अतिरिक्त करों का बोझ डाल दिया था और देश से पैसा बाहर निकालना शुरू कर दिया था।

सरकार को उम्मीद है कि नई, कम कर दरें देश में अधिक निवेश को आकर्षित करेंगी और घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में मदद करेंगी, जिसमें कमी देखी गई है।

इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

कर कटौती, निजी क्षेत्र के हाथों में अधिक पैसा लगाकर, लोगों को अर्थव्यवस्था के उत्पादन और योगदान के लिए अधिक प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है। इस प्रकार वर्तमान कर कटौती व्यापक अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद कर सकती है।

यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कॉर्पोरेट कर की दर, यह भी एक प्रमुख निर्धारक है कि कैसे निवेशक विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी आवंटित करते हैं। इसलिए दुनिया भर की सरकारों पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सबसे कम कर दरों की पेशकश करने का लगातार दबाव रहता है।

करों में वर्तमान कटौती भारत को पूर्वी एशिया में दरों की तुलना में भारतीय कॉर्पोरेट कर दरों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकती है। हालांकि, कर कटौती से सरकार को 1.45 लाख करोड़ रुपए का सालाना राजस्व नुकसान होने की आशंका है, जो अपने वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है।

उसी समय, यदि यह अर्थव्यवस्था को पर्याप्त रूप से पुनर्जीवित करने का प्रबंधन करता है, तो वर्तमान कर कटौती, कर संग्रह को बढ़ावा देने और राजस्व के नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकती है।

आगे क्या है?

कुछ लोग वर्तमान कर कटौती को केवल एक संरचनात्मक सुधार के रूप में कॉर्पोरेट घरानों को रियायत के रूप में देखते हैं जो व्यापक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। उनका मानना है कि मौजूदा आर्थिक मंदी अपर्याप्त मांग की समस्या के कारण है जिसे केवल कर कटौती के माध्यम से संबोधित नहीं किया जा सकता है और इसके बजाय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अधिक सरकारी खर्च की वकालत की जाती है।

हालांकि, अन्य लोगों का तर्क है कि ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में मांग की कमी महज आपूर्ति-पक्ष के कमजोर होने जैसे कि वस्तु और सेवा कर जैसे विभिन्न व्यवसायों को प्रभावित करने और रोजगार के नुकसान का कारण है। यदि हां, तो कर कटौती और अन्य आपूर्ति-पक्ष सुधार वास्तव में अर्थव्यवस्था को मंदी से उबरने में मदद कर सकते हैं।

हालांकि, सरकार को इन करों में कटौती के साथ-साथ अन्य संरचनात्मक सुधारों की भी आवश्यकता होगी, जो अर्थव्यवस्था में प्रवेश बाधाओं को कम करते हैं और बाजार को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। उदाहरण के लिए, सरकार छोटे व्यवसायों के लिए कर कटौती का विस्तार कर सकती है। वर्तमान कर कटौती के लाभ इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि सरकार लंबे समय में अपने वादों पर खरी उतरती है या नहीं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अतीत में निवेशकों का विश्वास अतीत में सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में पूर्वव्यापी परिवर्तन से प्रभावित रहा है।

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की है। कॉरपोरेट टैक्स कटौती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कॉरपोरेट टैक्स में कटौती आर्थिक वृद्धि में मंदी से निपटने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
2. इस कटौती से निजी क्षेत्र के हाथों में अधिक पैसा आने से अर्थव्यवस्था के उत्पादन और योगदान को प्रोत्साहन मिलेगा।
3. घरेलू कॉरपोरेट के लिए प्रभावी कर की दर 34.94% से गिरकर हो 25.17% हो जाएगी।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 3 (b) 1 और 2

(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Recently the government has cut corporate tax. Consider the following statements regarding corporate tax deduction:

1. Corporate tax cuts are an important step to deal with the slowdown in economic growth.
2. With more money coming into the hands of private sector by this deduction, the production and contribution of the economy will be encouraged.
3. Effective tax rate for domestic corporates will fall from 34.94% to 25.17%.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 3 (b) 1 and 2

(c) 2 and 3 (d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'केंद्रीय बजट 2019-20 में प्रस्तावित होने के बाद अभी हाल ही में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती को एक बड़ा और राहतकारी कदम बताया जा रहा है।' इसके पीछे उत्तरदायी कारण क्या है? इस कदम से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रत्यक्ष लाभ होंगे? **(250 शब्द)**

Q. Recently, the reduction in corporate tax after being proposed in the Union Budget 2019-20, is being described as a big and relief step. What is the responsible reason behind this? What direct benefits will the move have on the economy.

(250 Words)

नोट : 20 सितंबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।